जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 | वर्षः 21 | संख्याः 16 | प्रभात | जालोर, शुक्रवार 24 अप्रैल, 2026 | पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

‘भारतीय व चीनी लोग जो अमेरिका में आकर बसते हैं, ‘‘लैपटॉप वाले गुण्डे’’ हैं’

‘‘इन गुण्डों’’ ने हमें लूटा है तथा हमारे देश में ही हमको ‘‘सैकिण्ड क्लॉस’’ नागरिक बना दिया है’’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 अप्रेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का वह पॉडकास्ट फिर से शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारत, चीन और अन्य देशों को ‘‘नरक के गड्ढे’’ के रूप में वर्णित किया है। सैवेज ने अपने नस्लीय घृणापूर्ण बयान में अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि इन दो एशियाई देशों के लोग अमेरिका आते हैं, ‘‘नौवें महीने में बच्चा जन्म देने’’ के लिए, और यह कानून उन्हें ‘‘तुरंत’’ अमेरिकी नागरिक बना देता है।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने सैवेज के पॉडकास्ट ‘सैवेज नेशन’ का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की आलोचना की।

- ट्रंप ने राजनीतिक विचारक माइकल सैवेज के इस पॉडकास्ट को आगे शेयर व दुबारा रीपोस्ट करके, यह तो जता ही दिया कि वे पॉडकास्ट के इन विचारों को सही मानते हैं और अनुसरण करते हैं।
- इसी संदर्भ में ट्रंप ने यह भी उजागर किया कि वे इस व्यवस्था को एकदम गलत मानते हैं कि जो भी बच्चा, अमेरिका में पैदा हुआ है वह जन्मते ही अमेरिका का नागरिक हो जाता है।
- ट्रंप के अनुसार, इसी अजीबोगरीब व्यवस्था के कारण, गर्भावस्था के नवें महीने में, चीनी व भारतीय नागरिक अपनी महिलाओं को हवाई जहाज से अमेरिका भेज देते हैं, बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाने के लिए और बड़ा होने पर यह बच्चा अपने पूरे परिवार को अमेरिका ले आता है और अमेरिका का नागरिक बनवा देता है। अमेरिका की इस व्यवस्था को ट्रंप पूर्णतया बदल देना चाहते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें बाधक साबित हुआ तो वे ‘‘रैफ्रेंडम’’ के मार्फत इस व्यवस्था को बदल देंगे।

रेडियो होस्ट ने अमेरिका के गैर-नागरिक माता-पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने के विचार पर हमला किया और इस मुद्दे को अदालतों पर छोड़ने के बजाय राष्ट्रीय जनमत संग्रह की मांग की।

उन्होंने पत्र में लिखा, ‘‘यहाँ एक नवजात शिशु तुरंत नागरिक बन जाता है, और फिर वे पूरी फैमिली को चीन, भारत या पृथ्वी के अन्य किसी नरक के गड्ढे (देश) से अमेरिका में ले आते हैं।

पत्र में भारतीय और चीनी प्रवासियों को ‘‘लैपटॉप वाले गैंगस्टर’’ कहा गया, जिन्होंने ‘‘हमारे झंडे पर पांव रखा।’’

उन्होंने लिखा, ‘‘उन्होंने इस राष्ट्र को जितना नुकसान पहुँचाया है, उतना सभी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने 2 प्रतिशत महँगाई भत्ता बढ़ाया

जयपुर, 23 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को राज्य में महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य कार्मिकों एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी। इस निर्णय से लगभग 7.02 लाख कार्मिक एवं 5.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का

- इस निर्णय से 7.02 लाख राज्य कार्मिक तथा 5.44 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को आगामी जून में देय मई के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा 1 जनवरी से 30 अप्रेल तक चार माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनरों को 1 जनवरी, से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

अमेरिका में रह रहे 40 प्रतिशत भारतीय यूएस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं

कार्नेगी एंडाउमैंट और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट रिसर्च डेटा विश्लेषण फर्म यूगॉव द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे में यह निष्कर्ष निकला है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 अप्रेल। कई भारतीयों के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका कभी सबसे आकर्षक मंज़िल हुआ करता था, लेकिन अब कई लोगों के लिए अमेरिकी सपना धीरे-धीरे फीका पड़ रहा है। कार्नेगी एंडाओमैंट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय लगातार चिंतित हो रहा है, और कई अब अमेरिका छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ‘‘यू गव’’ के साथ मिलकर 1,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत भारतीय अमेरिकी लोगों ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबावों के कारण एमिग्रेशन के बारे में सोच चुके हैं।

सर्वे में बताया गया है, ‘‘एक छोटे समूह लगभग 14 प्रतिशत, का कहना है कि उन्होंने अक्सर अमेरिका छोड़ने के बारे में सोचा है, जबकि 26 प्रतिशत ने कभी-कभार इस बारे में सोचा है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक

- कुल एक हजार लोगों पर यह सर्वे किया गया। अमेरिका छोड़ने पर विचार कर रहे लोगों ने ट्रंप प्रशासन के प्रति अपनी गहरी नाखुशी जाहिर की।
- इनका कहना था कि ट्रंप प्रशासन की ‘‘अमेरिका फॉर अमेरिकन’’ नीति के कारण वे अलग-थलग सा महसूस करते हैं। यही नहीं नागरिकता संबंधी मसलों के कारण वे नौकरी और निवास को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे हैं।
- बढ़ती महँगाई ने भी आम मध्यमवर्गीय भारतीयों की तकलीफें बढ़ा दी हैं। सैनफ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में एक बेडरूम का घर 3 से 5 हजार डॉलर में मिलता है।

कारण अमेरिका की राजनीति से निराशा है, जिसे लगभग 10 में से 6 प्रतिभागियों (58 प्रतिशत) ने यही कारण बताया। इसके बाद जीवन-यापन की लागत (54 प्रतिशत) और व्यक्तिगत सुरक्षा (41 प्रतिशत) का कारण आता है।’’

ध्यान देने योग्य है कि आज अमेरिका में 52 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं।

इस बदलाव के पीछे राजनीतिक माहौल सबसे बड़ा कारण है, जिसमें 58 प्रतिशत लोगों ने इसे ही मुख्य वजह बताया। डॉनल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल से व्यापक असंतोष ने इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु व बंगाल से लगभग 1000 करोड़ की जब्ती हुई

चुनाव आयोग ने कहा, प.बंगाल में दूसरा चरण बाकी है, इसलिए यह राशि और बढ़ सकती है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 अप्रेल। चुनावों के दौरान की गई सबसे व्यापक प्रवर्तन कार्यवाहियों में से एक में, भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कुल जब्तियों की राशि पहले ही 1,072 करोड़ को पार कर चुकी है, जिससे यह चुनावों के दौरान की अब तक की सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्यवाही बन गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में कुल जब्तियाँ 599.24 करोड़ रुपये की दर्ज की गई हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में यह राशि 472.89 करोड़ रुपये है। इन आंकड़ों में जब्त की गई नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और ड्रग्स, कीमती धातुएँ और अन्य प्रलोभन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करना था।

इस जब्ती का स्वरूप दोनों राज्यों

- इस राशि में नकद पूँजी के साथ शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं व अन्य प्रलोभन शामिल हैं।
- प.बंगाल में 472.89 करोड़ रूपए की जब्ती हुई, वहीं तमिलनाडु में 599.24 करोड़ रूपए की। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 102.45 करोड़ रूपए की शराब जब्त हुई, जबकि तमिलनाडु में शराब के प्रति रूझान कम दिखा, मात्र 3.85 करोड़ रूपए की शराब जब्त हुई, यहाँ कीमती धातुओं के प्रति भारी रूझान दिखा और इनकी कुल 159.31 करोड़ रूपए की जब्ती हुई।

में अलग-अलग पैटर्न दिखाता है। पश्चिम बंगाल में, अधिकारियों ने 102.45 करोड़ रुपये की शराब और 108.11 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए हैं, इसके अलावा 178.83 करोड़ रुपये के फ्रीबीज़ और अन्य वस्तुएँ भी शामिल हैं। इसके विपरीत, तमिलनाडु में शराब की जब्ती अपेक्षाकृत कम, 3.85 करोड़ रुपये रही, लेकिन कीमती धातुओं की जब्ती 159.31 करोड़ रुपये और फ्रीबीज़ 259.14 करोड़ की रिकॉर्ड की गईं।

अधिकारियों ने संकेत दिया कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां मतदान का दूसरा चरण अभी बाकी है। सर्विलांस को मजबूत करने और त्वरित कार्यवाही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु में 84.31 प्रतिशत मतदान हुआ

चेन्नई, 23 अप्रैल (हि.स.)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। शाम लगभग 84.35 प्रतिशत रिकार्ड मतदान दर्ज किया गया। मतदान का समय शाम 6 बजे के बाद भी कई स्थानों पर मतदाताओं की लाइनें लगी

- शाम 6 बजे मतदान केन्द्रों पर लगी लाइनों को देखते हुए मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना।

देखी गईं। मतदान अधिकारी ने कतार में लगे लोगों को टोकन देकर मतदान कराया। अंत तक मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।

मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर पूरे दिन शाम 6 बजे तक चला। भीषण गर्मी के बावजूद युवा और महिलाएं लंबी कतारों में खड़े होकर उत्साह के साथ मतदान करते रहे। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को ‘‘पृथ्वी पर नरक’’ व भारतीयों को ‘‘लैपटॉप वाला गुण्डा’’ कहने पर भारी प्रतिक्रिया

अमेरिका के जापान में पूर्व राजदूत राहम इमानुअल ने कहा, ‘‘ट्रंप की यह टिप्पणी, भारत के मुँह पर थूकना है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा भारत और चीन को ‘‘नरक के गड्ढे’’ और सभी भारतीयों को ‘‘लैपटॉप वाले गैंगस्टर’’ कहे जाने वाले बयानों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की ‘‘चुप्पी’’ और ‘‘विरोध नहीं करने’’ के लिए विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की।

इसी बीच, रैम एमैनुअल, जो जापान में अमेरिकी राजदूत रहे हैं और 2028 के राष्ट्रपति पद के सम्भावित डेमोक्रैटिक उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ने ट्रम्प के भारत के प्रति इस रवैये की आलोचना की तथा कहा कि वॉशिंगटन ने सचमुच भारतीयों के चेहरे पर थूका है।’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने ट्रम्प की

- जैसा कि चर्चा है, राहम इमानुअल, 2028 में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए संभवतया डेमौक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
- देश में, विपक्षः कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आदि पार्टियाँ प्र.मंत्री मोदी को उकसा रहे हैं कि वे ट्रंप की टिप्पणी पर प्रबल विरोध व्यक्त करें।

टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा, ‘‘हमने कुछ रिपोर्टें देखी हैं’’, और आगे कहा, ‘‘मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ।’’

दिन की शुरुआत में, ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार माइकल सैवेज का पॉडकास्ट फिर से शेयर किया।

इस पॉडकास्ट में सैवेज ने भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को ‘‘नरक के गड्ढे’’ बताया। जहाँ ट्रम्प ने इसे साझा करते समय कोई कैप्शन नहीं जोड़ा, वहीं इसे अमेरिका में हाल ही में प्रवासन और घरेलू नीति पर उनकी बयानबाजी के अनुरूप माना जा रहा है।

भारत में, ट्रम्प के संदेश और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री से पूछा, ‘‘क्या आप इसका विरोध करेंगे, या बंगाल में अपनी अगली चुनावी रैली की ओर खी-खी (हँसी-ठिठोली) करते हुए चले जाएंगे?’’

कांग्रेस ने ट्रम्प की टिप्पणियों को ‘‘अत्यंत अपमानजनक और भारत विरोधी’’ बताया।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखाः ‘‘उनके (मोदी) ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे ट्रम्प के सामने कुछ कहेंगे। नरेन्द्र मोदी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, और पूरा देश इसे भुगत रहा है।’’

इस बीच, रैम एमैनुअल, जिन्होंने बराक ओबामा और जो बाइडन प्रशासन में विभिन्न पदों पर काम किया है, को यह कहते हुये उद्धृत किया गया हैः ‘‘ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका ने सचमुच भारत के चेहरे पर थूका है। भारत को अमेरिका के करीब लाना हर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए 30 साल का प्रोजेक्ट रहा है। मैं ट्रम्प जैसा कुछ नहीं करूंगा।’’

एसीडी तीन माह में जयपुर डिस्कॉम सीएमडी की जाँच रिपोर्ट दे- हाई कोर्ट

जयपुर 23 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद, उसे चार्जशीट देने और उसके बाद जांच रिपोर्ट पर निर्णय नहीं

- डिस्कॉम कर्मचारी का आरोप है कि जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्णय नहीं लेकर सीएमडी ने उसे पदोन्नति से वंचित किया।

करने के मामले में डिस्कॉम सीएमडी के खिलाफ एसीबी को तीन माह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं अदालत ने प्रमोशन के बिंदु पर मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पचास साल में पहली बार प.बंगाल में हुआ भारी 92 प्रतिशत मतदान

जाने माने राजनैतिक पर्यवेक्षक भी मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि से सकते में हैं, और इसे समझ नहीं पा रहे हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। लगभग पिछले पचास वर्षों को देखें तो इस बार एक बड़ा बदलाव दिखा, पहले चरण के चुनाव में अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने लोग बड़ी संख्या में बाहर आए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक वर्षों में पहली बार मतदान में व्यापक रक्तपात या हत्याओं जैसी घटनाएँ नहीं हुईं। केन्द्रीय बलों ने चुनाव से काफी पहले कई स्थानीय अपराधियों और गैंगस्टरों को हिरासत में ले लिया था।

तृणमूल नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने उनकी तुरंत रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जोरदार मुकदमा लड़ा था।

ऐसा लग रहा था, मानो लोग अपने मतों के माध्यम से इस लोकतांत्रिक अधिकार की अनदेखी का प्रतिशोध ले रहे हों, जिसे सत्तारूढ़ दलों, पहले वाम मोर्चा और बाद में तृणमूल कांग्रेस, के शासन ने नकारा था।

पहले चरण के चुनाव में 294 सीटों वाली राज्य विधानसभा की 154 सीटों के लिए मतदान हुआ। विशेष रूप से, महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया, कुछ ने इसे ‘‘अभया केस’’, आर.जी. कर अस्पताल में युवती डॉक्टर की हत्या, के जवाब के रूप में बताया।

मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं, जो तपती धूप में धैर्यपूर्वक अपने वोट डालने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और पूर्व चुनावों में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा दी गई

- पूर्व में प.बंगाल में मतदान के दौरान भारी हिंसा देखी जाती थी, पर, इस बार तुलनात्मक रूप से मतदान शांतिपूर्ण रहा, कुछेक घटनाएं हुईं, पर उन पर तुरंत एक्शन हुआ, मसलन भाजपा के एक प्रत्याशी सुभेन्दु सरकार को कुछ लोगों ने पीटा, उनके गार्ड ने उन्हें मुश्किल से बचाया, घटना का वीडियो देखकर चुनाव आयोग ने तुरंत कार्यवाही की और 20 लोग गिरफ्तार हुए।
- इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था से जनता में भरोसा बढ़ा और मतदान का प्रतिशत बढ़ता गया।
- पहले चरण में राज्य की 294 में से 154 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं, खासकर महिलाओं, की लंबी कतारें देखी गई। लोगों में इससे पहले के सत्तारूढ़ दलों, वाम मोर्चा और फिर तृणमूल, का आतंक इतना ज्यादा था कि मतदान के लिए कम ही लोग बाहर निकलते थे।
- इस बार चुनाव आयोग ने प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा था। भारी तादाद में केन्द्रीय बल तैनात किया गया। मतदान केन्द्रों पर कब्जे और फर्ज़ी मतदान पर पूर्ण अंकुश लगा दिया गया था।

धमकियों से आज़ाद थे। निर्वाचन आयोग ने हिंसा और मतदान केन्द्रों पर कब्ज़े या मतदाताओं को धमकाने की सभी रिपोर्टों को तुरंत ट्रैक करने में विशेष सावधानी बरती।

एक मामले में, भाजपा उम्मीदवार सुभेन्दु सरकार को कुमारगंज मतदान केन्द्र में तृणमूल के गुंडों ने बुरी तरह पीटा, और कैमरों ने उन्हें पीटते हुए कैद किया। उम्मीदवार को उनके एकमात्र गार्ड द्वारा मुश्किल से बचाया जा सका, जिसे खुद कई चोटें आईं।

भयानक हमलों से बाहर आने के बाद, सरकार और उनके बॉडीगार्ड को गांव की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया और भीड़ उनका पीछा कर रही थी।

घटना की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी गई, और कैमरे में कैद किए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 23 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने 2003 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के दोषी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को

- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र को एनसीपी नेता की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

मिली उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अमित जोगी की याचिका पर ये आदेश दिया।

अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। छत्तीसगढ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)